विचार बिन्दु

बिना जोश के आज तक कोई भी महान कार्य नहीं हुआ। –सुभाष चंद्र बोस

यूपीआई से मोहभंग का यथार्थ!

क्या यह बात कम विडंबनापूर्ण है कि डिजिटल भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय सुविधा यूपीआई के विरोध के स्वर उस शहर से उठ रहे हैं जिसे डिजिटल भारत का सर्वाधिक चमकदार चेहरा माना जाता है। ख़बर आई है कि बेंगलुरु के दुकानदारों ने अपनी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर इस आशय के बोर्ड लगाने शुरु कर दिए हैं कि वे केवल नकद भुगतान स्वीकार करेंगे, यूपीआई उन्हें स्वीकार्य नहीं है! हमारे पाठकों को यह बात याद होगी कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2015 को एक महत्वाकांक्षी पहल डिजिटल इण्डिया का शुभारम्भ किया था, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। यह कार्यक्रम तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित रहा है– 1. डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण, 2. इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाओं की डिलीवरी और 3. सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता।

इसके नौ स्तंभों में मोबाइल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच, ई-गवर्नेंस, और ई-क्रांति जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यह पहल भारतनेट, स्टार्टअप इंडिया, और मेक इन इंडिया जैसी अन्य योजनाओं के साथ तालमेल बिठाकर काम करती है। तो इसी डिजिटल इंडिया योजना के तहत नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा 2016 में यूपीआई की शुरुआत की गई। यूपीआई एक त्वरित और सुरक्षित भुगतान प्रणाली है जो 24/7 लेनदेन की सुविधा प्रदान करती है। डिजिटल इंडिया की अन्य योजनाओं और लक्ष्यों का क्या हश्र हुआ इस विस्तार में न जाते हुए हम फिलहाल यह याद रखें कि यूपीआई इस डिजिटल इंडिया सपने का सर्वाधिक चमकदार सितारा है। प्रारंभिक हिचकिचाहट के बाद अब कमोबेश पूरे देश ने इसे न केवल अपना लिया है, वह इसके उपयोग को सुविधाजनक भी मानने लगा है।

यूपीआई की प्रगति के बारे में अधिक जानने से पहले यूपीआई क्या है, यह जान लेना उपयुक्त होगा। यूपीआई (यूनिफाइडपेमेंट्स इंटरफेस) एक रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली है, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा विकसित किया गया है। यह बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं (PSPs), और उपयोगकर्ताओं के बीच एक एकीकृत मंच प्रदान करता है, जो त्वरित, सुरक्षित, और सुविधाजनक लेनदेन को सक्षम बनाता है। जहां तक यूपीआई के बढ़ते कदमों का सवाल है, यह जानना रोचक होगा कि अक्टूबर 2024 में यूपीआई के माध्यम से 16.58 अरब लेनदेन हुए, जिनका मूल्य 23.49 लाख करोड़ रुपये था। यह लेन-देन इससे पिछले वर्ष की तुलना में 45% अधिक था। 2024 में कुल 208.5 अरब डिजिटल लेनदेन दर्ज किए गए। इस यूपीआई लेन-देन ने छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी वालों, और प्रवासी श्रमिकों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। कोविड-19 महामारी के दौरान संपर्क रहित भुगतानों की मांग ने इसके उपयोग को और बढ़ाया। और उसके बाद यह जैसे हमारी आदत में ही शुमार हो गया। अब तो हालत यह है कि धार्मिक स्थल भी यूपीआई के माध्यम से दान स्वीकार करने लगे हैं और न केवल बहुत छोटे व्यवसायी, भिखारी तक यूपीआई का प्रयोग करने लगे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो सन् 2019 में जहां डिजिटल भुगतानों में यूपीआई की हिस्सेदारी मात्र 34 प्रतिशत थी वह 2024 में बढ़कर 84 प्रतिशत हो गई। इस वजह से भारत डिजिटल भुगतान के मामले में वैश्विक अग्रणी बन गया है। और केवल इतना ही नहीं, यूपीआई को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया जा रहा है। यूपीआई को सिंगापुर, यूएई और कुछ अन्य देश भी अपनाने जा रहे हैं।

हमारे देश में आम जन ने यूपीआई को इतने उत्साह से अपनाया है, इसके मूल में तीन ख़ास बातें हैं। पहली तो यह कि यूपीआई एक ही मोबाइल ऐप में कई बैंक खातों को जोड़ने की सुविधा देता है, जिससे उपयोगकर्ता बिना खाता संख्या या आईएफएससी कोड साझा किए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। दूसरी यह कि दो कारक प्रमाणीकरण की वजह से यूपीआई अपेक्षाकृत सुरक्षित और तेज लेनदेन सुनिश्चित करता है। और तीसरी यह कि छोटे लेनदेन के लिए यूपीआई लाइट जैसे विकल्पों ने कम मूल्य के भुगतानों को और सुलभ बना दिया है। और जैसे इतना पर्याप्त न हो, यूपीआई ने जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) त्रिमूर्ति के साथ मिलकर वंचित वर्गों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की है। अगस्त 2023 तक 50 करोड़ जन धन खाते खोले गए, जिनमें 56% महिलाओं के हैं। यूपीआई के कारण पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 23 लाख करोड़ रुपये का हस्तांतरण हुआ है, इसके अलावा यूपीआई ने छोटे और मध्यम उद्यमों (MEMEs) को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाया, जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं।

यूपीआई के विरोध के मूल में सबसे बड़ी बात इसका पारदर्शी होना है। यूपीआई से किया गया हर लेन देने रिकॉर्डेड होता है। अब अगर एक छोटा दुकानदार जो कल तक सारे टैक्स दायित्वों से बचा हुआ था वह आयकर विभाग या जीएसटी विभाग की निगाहों में आता है तो यह बात उसे पसंद नहीं आती है।

निश्चय ही यूपीआई की कुछ सीमाएं भी हैं। मसलन यह कि इसमें लेन-देन की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये है, यह पूरी तरह इंटरनेट की सुलभता पर निर्भर है और भारत में यह सुलभता कैसी है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके माध्यम से लेन-देन में सुरक्षा के भी कुछ ख़तरे हैं और समय-समय पर इसमें सेंधमारी कर लोगों को नुकसान पहुंचाने की ख़बरें भी आती रहती हैं। फिर भी इसे सुविधाजनक मान आम भारतीयों ने न केवल अपनाया है, अपनी आदत में भी शामिल कर लिया है। अब तो अगर आप नकद देना चाहें तो भी बहुत बार सामने वाला चलाकर कहता है कि आप यूपीआई से भुगतान कर दीजिए। फिर क्या वजह है कि बेंगलुरु जैसे अत्याधुनिक शहर के दुकानदार यूपीआई से गुरेज़ करने लगे हैं?

पहली बात तो यह है कि बार-बार आने वाली तकनीकी बाधाओं के कारण यूपीआई में बैकअप सिस्टम और पारदर्शिता की कमी है। इन तकनीकी समस्याओं ने कुछ उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों में असंतोष पैदा किया है। छोटे व्यापारी, जो पूरी तरह से यूपीआई पर निर्भर हैं, ऐसी समस्याओं से प्रभावित होते हैं और इसे अविश्वसनीय मान बैठते हैं। दूसरी बात यह कि यूपीआई की लोकप्रियता के साथ, फिशिंग, नकली यूपीआई ऐप्स, और क्यूआर कोड धोखाधड़ी जैसे साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है। उपयोगकर्ताओं को अक्सर फर्जी लिंक, फोन कॉल्स, या अनधिकृत भुगतान अनुरोधों के माध्यम से ठगा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और एनपीसीआई ने इसके खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए हैं, लेकिन फिर भी धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं और इनके कारण व्यापारियों का विश्वास डगमगाता है। बहुत बार उपयोगकर्ताओं की असावधानी से भी ग़लती हो जाती है। वे ग़लत पिन अंकित कर देते हैं या फर्जी क्यूआर कोड स्कैन करके अपना धन खो देते हैं, जिसके कारण वे यूपीआई का उपयोग करने से बचना चाहते हैं। फिर, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग यूपीआई को जटिल या अप्रासंगिक मानते हैं, क्योंकि उनके पास आवश्यक उपकरण (स्मार्टफोन) या ज्ञान नहीं है। कुछ समुदाय अभ्यास वश नकद लेनदेन को ही अधिक विश्वसनीय और सरल मानते हैं, जिसके कारण वे यूपीआई को अपनाने से हिचकते हैं।

लेकिन मुझे लगता है कि यूपीआई के विरोध के मूल में सबसे बड़ी बात इसका पारदर्शी होना है। यूपीआई से किया गया हर लेन देने रिकॉर्डेड होता है। अब अगर एक छोटा दुकानदार जो कल तक सारे टैक्स दायित्वों से बचा हुआ था वह आयकर विभाग या जीएसटी विभाग की निगाहों में आता है तो यह बात उसे पसंद नहीं आती है। इसी तरह जब एक नागरिक यूपीआई से भुगतान करता है तो उसका किया हुआ सारा भुगतान भी सरकार की नज़रों में आ जाता है। दो नंबर का धन रखने वालों को यह बात रास नहीं आती है इसलिए वे यूपीआई की बजाय नकद लेन देने को पसंद करते हैं। असल में हम लोग बहुत लम्बे समय से दो नंबरी अर्थ व्यवस्था के अभ्यस्त रहे हैं और वह हमें रास भी आती है। उस अर्थ व्यवस्था को छोड़ एक ऐसी अर्थ व्यवस्था को अपनाना जिसमें सब कुछ रिकॉर्डेड हो, लोगों को नहीं रुच रहा है। पहले वे इस बात को नहीं समझे थे, अब समझने लगे हैं। लेकिन यह जाना और समझा जाना चाहिए कि अगर यूपीआई के खिलाफ़ यही सबसे बड़ा तर्क है तो यह तर्क ग़लत है। सरकार अपनी कर प्रणाली को सरल करे, व्यापारी को बेवजह परेशान न होना पड़े, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इस बात का समर्थन कोई कैसे कर सकता है कि आप सारा लेन-देन दो नंबर में ही करते रहने की छूट चाहें? यह तो उनके प्रति भी अन्याय है जो ईमानदारी से कर चुकाते हैं। कोई छोटा व्यापार कर रहा है तो इसका यह अर्थ क्यों मान लिया जाए कि उस पर कोई नियम-कानून लागू ही न हो। हम तो सरकार से अपेक्षा करेंगे कि वह यूपीआई का विरोध करने वालों से संवाद करे और उनकी उचित दिक्कतों को समझ उनका निराकरण करते हुए उन्हें इस व्यवस्था के घेरे में रखने का हर संभव प्रयास करे। यह ज़रूरी है कि हम अपनी आय और व्यय के मामलों में ईमानदार हों और हम पर जो टैक्स की देनदारी बनती है उसे निष्ठापूर्वक चुकाएं।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाइयां एवं नकली खाद्य पदार्थ-सभी कुछ नकली

क्या सरकार असली कार्यवाही करेगी

सुनील दत्त गोयल

दवाइयों से लेकर बीज-खाद तक मिलावट का मायाजाल और कानून की ढीली गिरफ़्त

राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की हाल की छापामार कार्रवाई ने अचानक देश-भर में सावन के अंधेरे बादलों जैसे छाए नकली खाद-बीज के कारोबार को बिजली-सी रोशनी में ला खड़ा किया। जयपुर, किशनगढ़ और श्रीगंगानगर की 30 फ़ैक्ट्रियों से रोज़ाना दो-लाख से ज़्यादा नकली खाद की बोरियां निकल रहीं थीं, जिनमें संगमरमर का स्लरी, पत्थर-धूल और रंग मिलाकर 'ब्रांडेड' उर्वरक बनाया जा रहा था। यही जहर, उत्तर-भारत के खेतों में येन-केन-प्रकारेण पहुँच रहा था और उपजाऊ मिट्टी को बंजर बना रहा था।

दवा बाज़ार भी उतना ही बीमार है। आज भारत में एलोपैथिक दवाएं बाजार में 90 प्रतिशत तक की भारी छूट के साथ बेची जा रही हैं, लेकिन इस बेतहाशा छूट के पीछे इनकी गुणवत्ता अक्सर संदेह के घेरे में है। सस्ती और भारी छूट वाली दवाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि जब कंपनियाँ इतनी सस्ती दरों पर दवा बेचती हैं तो आम लोगों के मन में यह चिंता घर कर जाती है कि उनकी गुणवत्ता या तो घटिया है या फिर उनमें मिलावट की गई है। अखिल भारतीय केमिस्ट-ड्रगिस्ट संगठन ने चेताया कि कोविड-काल के बाद खुदरा बाज़ार में नकली-मिलावटी दवाइयों का हिस्सा 10 से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गया है। विनियामक सीडीएससीओ ने हाल ही में 63 आम दवाओं की असफल बैच सूची जारी की; यानी बीपी की गोली में उतना साल्ट ही नहीं जितना लेबल पर छपा था। रोगी की उम्मीदों पर नमक ही नमक, दवा नदारद! विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक लोग नकली और घटिया दवाओं से मरते हैं। इसका आर्थिक प्रभाव 21 अरब डॉलर वार्षिक है। विकासशील देशों में बेची जाने वाली 10.5 प्रतिशत दवाएं नकली या घटिया हैं। अफ्रीका में स्थिति और भी गंभीर है, जहां नकली मलेरिया रोधी दवाओं से हर साल 1.2 से 4.5 लाख लोग मरते हैं। भारत के संदर्भ में स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। डब्लु एच ओ की रिपोर्ट के अनुसार, एशिया की 35 प्रतिशत नकली दवाएं भारत से आती हैं। यूरोपीय आयोग की रिपोर्ट में तो यह दावा किया गया है कि विश्व के 75 प्रतिशत नकली दवाओं के मामले भारत से उत्पन्न होते हैं। भारत के प्रमुख शहरों में हर पांच दवा की पट्टी में से एक नकली है। इससे सालाना 4-5 प्रतिशत की आर्थिक हानि होती है। 2020-21 में नकली दवाओं की घटनाओं में 47प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2012 में कश्मीर में 300 बच्चों की मौत घटिया सेफ्ट्रिएक्सोन दवा से हुई, जो निमोनिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की गई थी। 2007 में महाराष्ट्र में 4 लोगों की मौत नकली दवाओं से हुई। नकली दवाओं का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वे दवा प्रतिरोध (ड्रग रेसिस्टेन्स) बढ़ाती हैं। जब मरीज़ों को पर्याप्त मात्रा में सक्रिय तत्व नहीं मिलता, तो बैक्टीरिया और वायरस इन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लु एच ओ) के ग्लोबोकान 2022 के अनुसार, भारत में कैंसर की स्थिति अत्यंत गंभीर है। 2022 में भारत में 14.1 लाख नए कैंसर के मामले सामने आए और 9.1 लाख लोगों की मृत्यु हुई। यह आंकड़ा भयावह है क्योंकि इसका मतलब है कि हर दिन लगभग 2,500 लोग कैंसर से मर रहे हैं।

दवा की दुकान खोलने के लिए बी.फार्मा की डिग्री का होना आवश्यक है, लेकिन वह व्यक्ति कहीं और नौकरी कर रहा होता है और अपना लाइसेंस किराए पर देता है। किराएदार उसके नाम पर दवा की दुकान चला रहा होता है। ऑक्सीटोसिन, कितना खतरनाक इंजेक्शन है जो कि पिछले लगभग 30 वर्षों से बनाना और बेचना पूर्णतया पूरे भारत में गैर कानूनी है, लेकिन यह बहुत सहज सुलभता से हर जगह उपलब्ध है और प्रत्येक दुधारू पशुओं में इसका बहुत उपयोग होता है। आजकल इसका उपयोग ऐसी सब्जियों में जिनको बहुत जल्दी बड़ा करना हो जैसे घीया, तुरई, तरबूज, खरबूजा, कद्दू या अन्य वह सब्जियां जिनको जल्दी फैलाना हो। इस तरह की सब्जियों में यह इंजेक्शन जड़ में या कोने में लगाते हैं और वह सब्जी दो से तीन दिन में बड़ी हो जाती है।

इसका असर यह होता है कि आजकल लड़कियों में बहुत कम उम्र में मासिक धर्म की समस्या होने लगी और जो महिलाएं मासिक धर्म में हैं उनको विकार उत्पन्न होने लगे। पेट की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, लीवर की बीमारियां इस तरह की अनेकों बीमारियां इस इंजेक्शन की वजह से होने लगी हैं। लेकिन ना तो ड्रग कंट्रोलर कोई ध्यान देता है ना ही फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले लोग ध्यान देते हैं, जबकि यह बहुत बड़ा अपराध है और यह बिल्कुल मृत्यु के अपराध के तुल्य है। कैंसर की बढ़ती दर के साथ-साथ नकली दवाओं की समस्या एक दोहरा संकट पैदा कर रही है। कैंसर की दवाएं नकली बनाने वालों का प्रमुख निशाना हैं क्योंकि ये महंगी होती हैं और इनकी मांग अधिक होती है। प्रतिशत

भारतीय कृषि में घटिया बीज एक बड़ा संकट बनता जा रहा है। कई बार किसान महंगे दामों पर बीज या पेड़ पौधे खरीद लेते हैं, लेकिन चार-पांच वर्ष बाद उन्हें पता चलता है कि वह गुणवत्ता विहीन था या सही नस्ल का था ही नहीं। इसका सीधा असर उसकी पूरी मेहनत, समय और धन पर पड़ता है-अर्थात किसान की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। यह स्थिति किसानों को आर्थिक रूप से और अधिक कमजोर बना देती है। किसानों से की गई धोखाधड़ी केवल किसी एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं रहती। जब किसान को घटिया या नकली सामग्री दी जाती है, तो न सिर्फ उनकी फसल या पशुधन बर्बाद होते हैं, बल्कि उसकी आजीविका पर भी गंभीर असर पड़ता है। सरकार की घोषणाएँ और कार्यवाही अक्सर केवल बातें ही साबित होती हैं, वास्तविकता में सुधार बहुत धीरे-धीरे या बिल्कुल नहीं हो रहा है।

केवल मानव चिकित्सा ही नहीं, पशु-पक्षियों की दवाएं, टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान (आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन) में भी भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। लेखक स्वयं रायला जिला भीलवाड़ा में डेयरी फार्म चला चुके हैं, जहां भैंस का सीमेन गायों में प्रयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप गाय समय पर गर्भवती नहीं हुई और मुझे व न जाने कितने गरीब, अशिक्षित किसानों को नुकसान झेलना पड़ा। इस व्यवस्था में अधिकारियों की मिलीभगत और भ्रष्टाचार के कारण पशुपालन क्षेत्र को गंभीर नुकसान हो रहा है।

मिलावट का आलम यह है कि देश में देशी घी की मिठाई सर्दी में जमती नहीं है और गर्मी में पिघलती नहीं है। फूड कलर्स का इस्तेमाल न करके पिगमेंट (फैक्टरियों में निर्मित, जिसमे पारे व अन्य अखाद्य पदार्थों का उपयोग होता है, से बनने वाले रसायन) का खुले तौर पर इस्तेमाल होता हैं। वही सारे पिगमेंट फूड क्लास में डालते हैं। केमिकल आने लग गए। समोसे में, नमकीन में, हल्दी, मिर्च और खटाई नकली डालने लग गए। जयपुर में जब छापे पड़े, मिठाई वालों के यहां भी, नकली हल्दी, मिर्च व खटाई पाई गई। या केमिकल पर, लिक्विड फॉर्मेशन में मिर्च के स्वाद जैसा कोई केमिकल पाया गया। तो आप कल्पना कीजिए, उत्पादक या दुकानदार किस स्तर तक गिर चुके हैं।

उत्पादक चाहे वह व्यापारी हो या किसान, उनका भी धर्म-ईमान का स्तर इतना गिर चुका है कि वे खतरनाक केमिकल्स व नकली सामानों का उपयोग अपने उत्पाद बनाने या उगाने में इतनी मात्रा में कर चुके हैं कि कैंसर एक भयावह रूप ले चुका है। और वे दोनों ही लोग-जो समाज, देश और धरती की ज़िम्मेदारी में सहभागी हैं-वे भूल चुके हैं कि इन सामानों का उपभोग उनके अपने लोग, उनके नातेदार, रिश्तेदार भी कहीं ना कहीं किसी रूप में कर रहे होंगे और वे भी इसके द्वारा प्रभावित होंगे और उसके नुकसान से बच नहीं सकते। भारतीय खाद्य व्यवस्था में मिलावट का आलम यह है कि अब खटाई के लिए प्राकृतिक सामग्री की जगह नमक का तेज़ाब (एसिटिक एसिड) का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह औद्योगिक रसायन, जो मूल रूप से सफाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग होता है, अब सीधे लोगों के पेट में जा रहा है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि पाचन तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।

बाजार में मिलने वाली मीठी सोंठ की चटनी में असली सोंठ का नामोनिशान तक नहीं है। इसकी जगह रंग और केमिकल मिलावट का भंडार है-न गुड़ है, न आमचूर। यह पूरी तरह से कृत्रिम स्वाद, रंग और सुगंध से तैयार की गई नकली चटनी है जो स्वाद की आड़ में जहर परोस रही है। इसी तरह हरी चटनी में धनिया की जगह हरा रंग और केमिकल का घोल है, जो धनिया के स्वाद का भ्रम पैदा करता है। घरेलू रसोई की जान माने जाने वाले हल्दी और धनिया पाउडर भी अब नकली हो गए हैं। इन मसालों में असली हल्दी और धनिया की जगह रंग, स्टार्च और अन्य सस्ते विकल्प मिलाए जा रहे हैं। यह न केवल पोषण मूल्य को नष्ट करता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व भी शामिल करता है।

सबसे खतरनाक बात यह है कि खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल हो रहे पिगमेंट्स का आधार पारा (मर्करी) होता है। पारा एक अत्यंत विषैला तत्व है जो तंत्रिका तंत्र, किडनी और लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। लंबे समय तक इसका सेवन कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और मानसिक विकारों का कारण बनता है। यह स्थिति इतनी गंभीर है कि इसे धीमी हत्या के समान माना जाना चाहिए।

दवा कंपनियों के अशुद्ध या नकली उत्पाद बाज़ार में आने के लिए कंपनी, उसके हर जिम्मेदार कर्मचारी एवं प्रबंधन की सीधी ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए। ऐसे मामलों में सिर्फ लाइसेंस रद्द कर देना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि इस कृत्य को हत्या के प्रयास के अपराध के तहत मानते हुए सख्त सजा मिलनी चाहिए। साथ ही, सभी बिक्री केंद्रों पर बी.फार्मा डिग्रीधारी का स्वयं का होना अनिवार्य बनाया जाए जिससे कमीशन एजेंटों और अनट्रेंड सेल्समैन द्वारा, बिना किसी जांच के दवाएं न बेची जा सकें।

मानव चिकित्सा, कृषि और पशुपालन क्षेत्र में चल रहे इन संगठित घोटालों को जनसंहार के प्रयास के रूप में लिया जाना चाहिए। पूरे नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति-कंपनी मालिक, कर्मचारी, बिचौलियों, अधिकारियों-को कड़ी सजा और आजीवन प्रतिबंध मिलना चाहिए। जब तक ऐसी घटनाओं का कानूनी और सामाजिक स्तर पर कठोर दमन नहीं होगा, तब तक देश की सेहत, किसान और पशुधन, सबका भविष्य खतरे में बना रहेगा।

सरकार क्या करे?

केन्द्र-राज्य टास्क फ़ोर्स: रैपिड एक्शन के लिए कृषि, स्वास्थ्य और उपभोक्ता मामलों का संयुक्त दस्ता बने।

जन-सूचना ऐप: किसान-रोगी एक क्लिक में बैच-नंबर डालकर असली-नकली पहचानें; शिकायत दर्ज होते ही 24 घंटे के भीतर छापा अनिवार्य हो।

निष्कर्ष:– नकली खाद, बीज और दवाइयाँ-तीनों हमारे खेत-खलिहान और शरीर की जड़ पर एक साथ प्रहार हैं। राजस्थान में हुई कार्रवाइयाँ इस लड़ाई की महज़ शुरुआती झलक हैं। दवा, बीज, खाद और कीटनाशकों की मिलावट व नकली उत्पादों के पीछे अक्सर सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत पाई जाती है। नमूना के तौर पर, एक ट्रेन का नाम 'पंजाब कैंसर एक्सप्रेस' जैसे उपनाम सामने आए हैं जो घटिया खाद, बीज और कीटनाशकों के उपयोग व उपभोग के कारण पंजाब में बड़ी संख्या में कैंसर मरीजों के लिए जिम्मेदार है। इन समस्याओं के बावजूद, कृषि व औषधि उत्पादों की दुकानों पर आज भी कड़े कानूनों का अभाव है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।

असली न्याय तभी होगा, जब मिलावटख़ोरों को 'लागत-जोखिम' गणित में साफ़ दिखे कि जेल-यातना और आजीवन बहिष्कार उनका तय भविष्य है। वरना नकली का कारोबार यूँ ही फलता-फूलता रहेगा और असली ज़िंदगियाँ धीरे-धीरे मिट्टी होती रहेंगी।

–सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल
चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया

छायादार व दीर्घायु पौधे लगाए, चिकित्सकों की टीम भी पौधारोपण में जुटी

नागौर, (निसं)। नागौर जिला मुख्यालय के निकटवर्ती श्याम विहार कॉलोनी में नगर के अनेक नागरिकों ने पौधारोपण किया। कॉलोनी के समीप पड़ी खाली भूमि पर यह पौधारोपण किया गया जिसके पास में कॉलोनी वासियों द्वारा पूर्व में ही विविध प्रकार के पौधे लगाए गए। पर्यावरणविद् सुखराम चौधरी, डॉ. के.आर.गौड, डॉ. मूलाराम जांगू व ठेकेदार कानाराम सिंवर के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया जिसमें 100 से अधिक पौधे लगाये गये। पर्यावरण गतिविधि के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन अपना संस्थान के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों का भी इसमें सहयोग रहा। इस अवसर पर कोलोनीवासियों के साथ साथ तथा डॉ. शंकरलाल जाखड़, डॉ. मूलाराम जांगू, ओमप्रकाश फौजी, ओमप्रकाश बिश्नोई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर संघचालक मांगीलाल बंसल, डॉ. केवलराम गौड, डॉ. सुरेन्द्र सिंह राठौड़, डॉ. भंवरलाल बिस्सु, नागरचंद भार्गव, बालकिशन, प्रभुराम धुंधवाल, हनुमान सिंह चारण, शिवशंकर व्यास, डॉ. शंकर पूनिया व कैलासदास सहित अनेक नागरिक व कार्यकर्ताओं की पौधरोपण में सहभागिता रही। अभियान में बालक गौरव राव व कनक ने भी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया।

नागौर नगर परिषद सभापति मीतू बोथरा ने शहरवासियों के साथ पौधे लगाए।

वहीं चेनार गांव में गांव के वरिष्ठजनों, युवा शक्ति, नारी शक्ति व बालक बालिकाओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। जिसमें नवयुवकों द्वारा आज 51 पेड़ और लगाए गए। इस वृक्षारोपण अभियान में संत लिखमीदास गौशाला चेनार के सदस्य व पर्यावरण पंकज टाक, राधेश्याम टाक, कमल पंवार, अनिल टाक, शिव टाक, दिनेश टाक, गुलाबचन्द, राम किशोर, लालू टाक एवं रिटायर फोरमैन भंवर लाल टाक, छोटमल टाक सहित सभी कार्यकर्ताओं ने पेड़ लगाकर इस अभियान में सहयोग किया।

वहीं शहर के बख्तसागर पार्क में मानसून सीजन के बीच रविवार को सघन पौधरोपण किया गया। नगर परिषद सभापति मीतू बोथरा ने बड़ी संख्या में शहरवासियों के साथ-साथ फलदार, फूलदार और छायादार पौधे लगाए। बख्तसागर पार्क में रविवार को सभापति मीतू बोथरा की अगुवाई में विभिन्न किस्मों के करीब 200 फलदार, फूलदार और छायादार पौधे लगाए गए। इस दौरान सभापति बोथरा ने कहा कि मानसून सीजन में पौधे लगाने से पौधों की अच्छी बढ़ोतरी होती है. साथ ही आने वाले समय में यहां आने वाले लोगों को सुगंधित और हरियाली से आच्छादित माहौल मिल सकेगा. इस दौरान देवकिशन जाट, नवीन बांठिया, राजेन्द्र नाहटा, लक्ष्मण पंवार, प्रदीप डागा, विमलेश बोथरा, पुखराज सेन, विष्णु वर्मा, दयाराम भाटी, जेठाराम सेन, मो. असगर, गणपत सेन, आयुष पंवार, हरिराम भाटी सहित अनेक शहरवासी मौजूद थे।

राजसमंद में बेटियों ने अपनी माताओं के साथ पौधारोपण किया : राजसमंद में मेरा युवा भारत राजसमंद और स्वामी विवेकानंद युवा मंडल स्वच्छ केलवा-हरित केलवा की पहल के तहत एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण कार्यक्रम राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोली बावडी कचोलिया में संपन्न हुआ। युवा मंडल अध्यक्ष लालूराम सिंधल ने बताया कि 21 बेटियों ने अपनी माताओं के साथ पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया।

अभियान का उद्देश्य मातृ-प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त करना और भावी पीढियों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिला प्रमुख सोहनी देवी गुर्जर और अध्यक्षता माय भारत राजसमंद के जिला युवा अधिकारी हेमंत कुमार मथुरिया ने की। विशिष्ठ अतिथि कार्यकम अधिकारी हनवंत सिंह चौहान, हिम्मत सिंह थे। संयोजक अशोक माली ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न छायादार पौधों का रोपण किया गया।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 21 जुलाई, 2025

सावन मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2082, रोहिणी नक्षत्र रात्रि 9:07 तक, वृद्धि योग सायं 6:39 तक, बालव करण प्रात: 9:39 तक, चन्द्रमा आज वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क चन्द्रमा-वृष, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज कुमार योग सूर्योदय से दिन 9:34 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। अमृत सिद्धि योग रात्रि 9:07 से सूर्योदय तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:30 तक, शुभ 9:11 से 0:52 तक, चर 2:14 से 3:55 तक। लाभ-अमृत 3:55 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 5:49, सूर्यास्त 7:17

मेष
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।

वृष
व्यावसायिक-आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

मिथुन
आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। धन हानि हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा। घर-गृहस्थी के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

कर्क
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

कन्या
नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। यावसायिक परेशानियां अभी बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

वृश्चिक
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
स्वास्थ्य में सुधार होगा।